लखनऊ में भी डाटा सेंटर बनाया जाएगा

सहमति

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश में राज्य डाटा सेंटर नीति के तहत तय लक्ष्य दो वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेने की उम्मीद है। इसी वर्ष जनवरी में जारी डाटा नीति के तहत पांच हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर सहमति बन चुकी है। वहीं लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें हीरानंदानी समेत अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस कॉरपोरेट आईटी पार्क लि., कंट्रोल एस, अमेजन इंटरनेट सर्विस प्रा.लि. समेत कई कम्पनियां शामिल हैं। इनमें दो डाटा सेंटर लखनऊ में बनाने के प्रस्ताव भी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इनमें चार कम्पनियों के पांच हजार करोड़ के प्रस्ताव पर मंजूरी चुनावों से पहले जारी हो सकती है। इनमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा व लखनऊ के लिए प्रस्ताव 2 आए हैं। 13 निवेशकों के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। इनमें उपरोक्त कम्पनियों के अलावा नेटमैजिक आईटी सर्विस प्रा लि, नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड, सिफी टेक्नोलॉजीस लि., वेबवर्क्स इण्डिया प्रा लि. ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रा. लि. साइफ्यूचर इण्डिया प्रा लि. जैसी कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही हैं।

क्या होता है डाटा सेंटर

भारत में पर्याप्त डाटा सेंटर न होने के कारण यूपी समेत अन्य राज्यों का डाटा विदेशों में रखा जाता है। डाटा सेंटर, नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है। बड़ी मात्रा में डाटा भंडारण, प्रोसेसिंग और वितरण के लिए विभिन्न कम्पनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। बैंकिंग, रिटेल व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन, आधार कार्ड समेत विभिन्न सोशल साइट्स पर लोगों का डाटा मौजूद रहता है। इन्हें सुरक्षित तरीके से भण्डारण करना बड़ी चुनौती है।